भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2286** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

समुद्री क्षेत्र में रोजगार के अवसर

†2286. डॉ. संजय जायसवाल :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री क्षेत्र में रोजगार के 50,000 अवसरों के सृजन हेतु प्रस्तावित योजना के लिए कोई व्यवहार्यता या प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विशिष्ट सामुद्रिक कौशलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गुवाहाटी स्थित सामुद्रिक कौशल विकास केन्द्र और डिब्रूगढ़ में स्थापित किए जाने वाले उत्कृष्टता केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) डिब्रूगढ़ में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय और वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं तथा इसके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) सृजन हेतु प्रस्तावित 50,000 सामुद्रिक नौकरियों में सरकार द्वारा सभी आठ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए समान अवसर किस प्रकार सुनिश्चित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): आत्मनिर्भर भारत पहल के भाग के रूप में आने वाले वर्षों में समुद्री शहरों की तरह द्वीपों के विकास पर फोकस किया गया है। विकास के लिए चुने गए द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा गुजरात राज्य में हैं। विकास के विषयों में पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाएं, पोत मरम्मत, समुद्री योजना निर्माण और मरम्मत, समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, मुक्त व्यापार क्षेत्र और बंकरिंग टर्मिनल शामिल हैं। परिकल्पित विकास से द्वीपों पर 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

(ग): समुद्री कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी), गुवाहाटी, समुद्री सुरक्षा, अंतर्देशीय जलयान प्रबंधन अर्थात सामान्य प्रयोजन रेटिंग पाठ्यक्रम, चालक दल प्रबंधन, आतिथ्य, सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। डिब्रूगढ़ में आगामी क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आरसीओई) पर पाठ्यक्रमों में नियमानुसार आधारभूत अंतर्देशीय जलमार्ग पाठ्यक्रमों के अलावा स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम, समुद्री इंजीनियरिंग, आईटी और लॉजिस्टिक्स जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण शामिल है।

(घ): सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से डिब्रूगढ़ में आरसीओई की स्थापना के लिए कुल अनुमानित लागत 188 करोड़ रुपए है और परियोजना को पूरा करने में 19 महीने का समय लगेगा।

(ङ): पूर्वोत्तर क्षेत्र के दोनों केंद्रों का उद्देश्य आठ पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश के भावी प्रशिक्षणार्थियों को अवसर प्रदान करना है।

*****